

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025—पौष 26, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. 1134-5-इक्कीस-अ (प्रा.)- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम (क्रमांक २ सन् २०२५)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२४

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा ६ का संशोधन
३. धारा १० का संशोधन
४. धारा ११-क का अंतःस्थापन.
५. धारा १३ का संशोधन.
६. धारा १६ का संशोधन.

७. धारा १७ का संशोधन.
८. धारा २१ का संशोधन.
९. धारा ३० का संशोधन.
१०. धारा ३१ का संशोधन.
११. धारा ३५ का संशोधन.
१२. धारा ३६ का संशोधन.
१३. धारा ४६ का संशोधन.
१४. धारा ५० का संशोधन.
१५. धारा ५१ का संशोधन.
१६. धारा ५४ का संशोधन.
१७. धारा ६१ का संशोधन.
१८. धारा ६२ का संशोधन.
१९. धारा ६३ का संशोधन.
२०. धारा ६४ का संशोधन.
२१. धारा ६५ का संशोधन.
२२. धारा ६६ का संशोधन.
२३. धारा ७० का संशोधन.
२४. धारा ७३ का संशोधन.
२५. धारा ७४ का संशोधन.
२६. धारा ७४क का अंतःस्थापन.
२७. धारा ७५ का संशोधन.
२८. धारा १०४ का संशोधन.
२९. धारा १०७ का संशोधन.
३०. धारा ११२ का संशोधन.
३१. धारा १२२ का संशोधन.
३२. धारा १२७ का संशोधन.
३३. धारा १२८क का अंतःस्थापन.
३४. धारा १७१ का संशोधन.
३५. अनुसूची ३ का संशोधन.
३६. संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२५

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२४

[दिनांक १५ जनवरी, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जनवरी, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) का धारा ६ में, उपधारा (१) में, शब्द "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" के पश्चात्, शब्द "और विकृत अतिरिक्त निष्प्रभावी ऐल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है," अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (५) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १० का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

"११क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,-

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी प्रदाय पर राज्य कर के उद्ग्रहण जिसमें उसकी उद्ग्रहण सम्मिलित है के संबंध में कोई पद्धति साधारणतया प्रचलन में थी या है; और

(ख) ऐसी प्रदाय, जो निम्नलिखित के लिए दायी थी या है -

(एक) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या

(दो) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्ग्रहीत किया जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है, तो राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी प्रदाय पर संदेय संपूर्ण राज्य कर या ऐसी प्रदाय पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन प्रदाय के संबंध में संदेय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्ग्रहीत किया जा रहा है."

धारा ११क का अंतःस्थापन. साधारण पद्धति के परिणामस्वरूप उद्ग्रहीत नहीं किए गए या कम उद्ग्रहीत किए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति.

५. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (३) में, -

(एक) खण्ड (ख) में, शब्द "प्रदायकर्ता द्वारा" के स्थान पर, शब्द "उन मामलों में, जहां बीजक प्रदायकर्ता द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, प्रदायकर्ता द्वारा", स्थापित किए जाएं तथा शब्द "पश्चात्तवर्ती तारीख" के पश्चात्, शब्द "या" स्थापित किए जाएं.

धारा १३ का संशोधन.

(दो) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, प्राप्तकर्ता द्वारा जारी किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख:”;

(तीन) पहले परंतुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “या खण्ड (ख) ” के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “या खण्ड (ग)” अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा 96 का 6. मूल अधिनियम की धारा 96 में 9 जुलाई, 2019 से, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“(5) उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2019-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 से संबंधित, माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 36 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा.

(6) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 26 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात् या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरण किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (8) के अधीन निर्बन्धित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 36 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो-

(एक) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात् आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है, सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, फाइल की जाती है; या

(दो) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से, उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, फाइल की जाती है.”.

धारा 97 का 7. मूल अधिनियम की धारा 97 में उपधारा (5) में, खण्ड (झ) में, शब्द और अंक “धारा 98, धारा 92E और धारा 930” के स्थान पर, शब्द और अंक “वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 98” स्थापित किए जाएं,

धारा 29 का 8. मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द और अंक “धारा 93 या धारा 98”, के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 98क” अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा 30 का 9. मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में परंतुक के पश्चात्, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं.”.

धारा 31 का 10. मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (3) में,-

(क) खण्ड (च) में, शब्द तथा अंक “कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो “धारा 6 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है”, के पश्चात्, शब्द “ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए” अंतःस्थापित किए जाएं.”

(ख) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण—खण्ड (च) के प्रयोजनों के लिए, "ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" पद के अंतर्गत ऐसा प्रदायकर्ता भी होगा, जो केवल धारा ५१ के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत है."

११. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (६) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ३५ का संशोधन.
१२. मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ३६ का संशोधन.
 "(३) धारा ५१ के अधीन, स्रोत पर कर कटौती के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा :
 परंतु उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियां की गई हों अथवा नहीं."
१३. मूल अधिनियम की धारा ४६ की उपधारा (८) में, खण्ड (ग) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और "अक्षर" या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ४६ का संशोधन.
१४. मूल अधिनियम की धारा ५० की उपधारा (१) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", शब्दों और अंकों के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ५० का संशोधन.
१५. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (७) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर"या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ५१ का संशोधन.
१६. मूल अधिनियम की धारा ५४ में,— धारा ५४ का संशोधन.
 (क) उपधारा (३) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाए ;
 (ख) उपधारा (१४) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
 "(१५) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की प्रदाय की शून्य रेटेड के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड प्रदाय के मद्दे संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य रेटेड प्रदाय निर्यात शुल्क के अध्यधीन है."
१७. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (३) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ६१ का संशोधन.
१८. मूल अधिनियम की धारा ६२ में उपधारा (१) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ६२ का संशोधन.
१९. मूल अधिनियम की धारा ६३ में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ६३ का संशोधन.
२०. मूल अधिनियम की धारा ६४ में, उपधारा (२) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ६४ का संशोधन.
२१. मूल अधिनियम की धारा ६५ में, उपधारा (७) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ६५ का संशोधन.
२२. मूल अधिनियम की धारा ६६ में, उपधारा (६) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४", के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर"या धारा ७४क", अंतःस्थापित किए जाएं. धारा ६६ का संशोधन.

धारा ७० का २३. मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्:- संशोधन.

(१क) "उपधारा (१) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्ध होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निर्देश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हों, प्रस्तुत करेगा."

धारा ७३ का २४. मूल अधिनियम की धारा ७३ में,- संशोधन.

(एक) पार्श्वशीर्ष में, शब्द "इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" के पश्चात्, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे."

धारा ७४ का २५. मूल अधिनियम की धारा ७४ में,- संशोधन.

(एक) पार्श्वशीर्ष में, शब्द "इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण" के पश्चात्, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित" अंतःस्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (११) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२३-२४ तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे."

(तीन) स्पष्टीकरण २ का लोप किया जाएगा.

धारा ७४क का २६. मूल अधिनियम की धारा ७४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :- अंतस्थापन.

वित्तीय वर्ष २०२४-२५ से तथा उससे आगे किसी कारण से असंदत्त या कम संदत्त कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.

"७४क. (१) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, के साथ हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप शास्ति का संदाय करे.

परंतु यदि वह कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार रुपये से कम है, तो सूचना जारी नहीं की जाएगी.

(२) समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन सूचना उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर जारी करेगा.

(३) जहां उपधारा (१) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है, तो समुचित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा.

(४) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (१) से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए, लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(५) उस मामले में जहाँ किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, शास्ति,—

(एक) ऐसे व्यक्ति से देय कर का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न कोई अन्य कारण है;

(दो) ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण है;

(६) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देयकर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(७) समुचित अधिकारी उपधारा (६) के अधीन आदेश उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर जारी करेगा।

परंतु जहाँ समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है, वहाँ आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से वरिष्ठ परंतु संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद से नीचे का न हो, उपधारा (६) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उक्त अवधि को अधिकतम छह माह के लिए आगे बढ़ा सकेगा।

(८) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

(एक) उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारण किए गए कर के आधार पर धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में यथास्थिति, उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना या उपधारा (३) के अधीन कोई विवरण, तामील नहीं करेगा;

(दो) धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

(९) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहाँ इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,—

(एक) उपधारा (१) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के निर्धारण के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना

समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगा;

(दो) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी.

(तीन) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी.

(१०) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (८) के खंड (एक) या उपधारा (६) के खंड (एक) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (१) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा.

(११) उपधारा (८) के खंड (एक) या खंड (दो) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (५) के खंड (एक) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है.

(१२) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष २०२४-२५ से तथा उससे आगे कर के निर्धारण के लिए लागू होंगे.

स्पष्टीकरण १ – इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) पद "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा १३२ के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(दो) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है, और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है, तो धारा १२२ और धारा १२५ के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण २ – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिसे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा.

धारा ७५ का संशोधन. २७. मूल अधिनियम की धारा ७५ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०)" के पश्चात, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या ७४क उपधारा (२) और (७)" स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (२) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा ७४क की उपधारा (५) के खंड (दो) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा ७४क की उपधारा (५) के खंड (एक) के अधीन होगा.";

(ग) उपधारा (१०) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१०) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा ७३ की उपधारा (१०) या धारा ७४ की उपधारा (१०) या धारा ७४क की उपधारा (७) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है.;"

(घ) उपधारा (११) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा ७४ की उपधारा (१०)" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या धारा ७४क की उपधारा (७)" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ङ) उपधारा (१२) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं;

(च) उपधारा (१३) में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

२८. मूल अधिनियम की धारा १०४ की उपधारा (१) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "या धारा ७४ की उपधारा (२) और उपधारा (१०)" के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या ७४क की उपधारा (२) और (७)" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १०४ का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की धारा १०७ में,—

धारा १०७ का संशोधन.

(क) उपधारा (६) में, खंड (ख) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर, शब्द "बीस" स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (११) में, दूसरे परंतुक में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

३०. मूल अधिनियम की धारा ११२ में,—

धारा ११२ का संशोधन.

(क) १ अगस्त, २०२४ से, उपधारा (१) में, शब्द "उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से" के पश्चात्, शब्द "या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्तवर्ती हो" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ख) १ अगस्त, २०२४ से, उपधारा (३) में, शब्द "उक्त आदेश पारित किया गया है" के पश्चात्, शब्द "या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चात्तवर्ती हो" अंतःस्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (६) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्", के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अंक "या उपधारा (३) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्" तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा" अंतःस्थापित किए जाएं;

(घ) उपधारा (८) के खंड (ख) में,—

(एक) शब्द "बीस प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "दस प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(दो) शब्द "पचास करोड़ रुपए" के स्थान पर, शब्द "बीस करोड़ रुपए" स्थापित किए जाएं.

३१. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उपधारा (१ख) में, १ अक्टूबर, २०२३ से शब्द जो "कोई भी इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक," के स्थान पर, शब्द और अंक "कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा ५२ के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है," स्थापित किए जाएं.

धारा १२२ का संशोधन.

३२. मूल अधिनियम की धारा १२७ में, शब्द और अंक "धारा ७३ या धारा ७४" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा ७४क" अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा १२७ का संशोधन.

धारा १२८क का अंतःस्थापन.
कतिपय कर अवधियों के लिए, धारा ७३ के अधीन की गई मांगों से संबंधित ब्याज या शास्ति या दोनों का अधिव्यजन.

३३. मूल अधिनियम की धारा १२८ के पश्चात, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

"१२८क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,-

- (क) धारा ७३ की उपधारा (१) के अधीन जारी सूचना या धारा ७३ की उपधारा (३) के अधीन जारी कथन और जहां धारा ७३ की उपधारा (६) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या
- (ख) धारा ७३ की उपधारा (६) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा १०७ की उपधारा (११) या धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या
- (ग) धारा १०७ की उपधारा (११) या धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा ११३ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

१ जुलाई, २०१७ से ३१ मार्च, २०२० की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा ५० के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी;

परंतु जहां धारा ७४ की उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा ७५ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा:

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा १०७ की उपधारा (३) या धारा ११२ की उपधारा (३) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा ११७ की उपधारा (१) के अधीन या धारा ११८ की उपधारा (१) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध या पहले परंतुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध धारा १०८ की उपधारा (१) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है :

परंतु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा.

- (२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्दे किसी व्यक्ति के द्वारा संदेय किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी.
- (३) उपधारा (१) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है.
- (४) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा १०७ की उपधारा (१) या धारा ११२ की उपधारा (१) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (१) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी."

३४. मूल अधिनियम की धारा १७१ में,—

धारा १७१ का संशोधन.

(क) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है.

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “परीक्षा के लिए अनुरोध” से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है.”;

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण १ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण १ के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

‘स्पष्टीकरण २— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद “प्राधिकारी” के अंतर्गत “अपील अधिकरण” सम्मिलित होगा.

३५. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में, पैरा ८ के पश्चात् और स्पष्टीकरण १ के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्

अनुसूची ३ का संशोधन.

“६. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रदाय की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप.

१०. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनःबीमाकर्ता, बीमाकर्ता द्वारा उक्त अध्यापित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन सहित संदत्त सकल पुनः बीमा प्रीमियम पर केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यापित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन पुनः बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है.”.

३६. उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं गया होता, यदि इस अधिनियम की धारा ६ सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती.

संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय न किया जाना.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. 1134-5-इक्कीस-अ (प्रा.)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 of 2025

THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(THIRD AMENDMENT) ACT, 2024

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 9.
3. Amendment of Section 10.
4. Insertion of Section 11A.
5. Amendment of Section 13.
6. Amend'ment of Section 16.
7. Amendment of Section 17.
8. Amendment of Section 21.
9. Amendment of Section 30.
10. Amendment of Section 31.
11. Amendment of Section 35.
12. Amendment of Section 39.
13. Amendment of Section 49.
14. Amendment of Section 50.
15. Amendment of Section 51.
16. Amendment of Section 54.
17. Amendment of Section 61.
18. Amendment of Section 62.
19. Amendment of Section 63.
20. Amendment of Section 64.
21. Amendment of Section 65.
22. Amendment of Section 66.
23. Amendment of Section 70.
24. Amendment of Section 73.
25. Amendment of Section 74.
26. Insertion of Section 74A.
27. Amendment of Section 75.
28. Amendment of Section 104.
29. Amendment of Section 107.
30. Amendment of Section 112.
31. Amendment of Section 122.
32. Amendment of Section 127.
33. Insertion of Section 128A.
34. Amendment of Section 171.
35. Amendment of Schedule III.
36. No refund of paid tax and reversed input tax credit.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 2 OF 2025
THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(THIRD AMENDMENT) ACT, 2024

[Received the assent of the Governor on the 15th January, 2025; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 16th January, 2025.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by Madhya Pradesh Legislature in the seventy-fifth year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|--|---|
| 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2024. | Short title and commencement. |
| (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. | |
| 2. In Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted. | Amendment of Section 9. |
| 3. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (5), after the words and figures "Section 73 or Section 74", the words, figures and letter "or Section 74A" shall be inserted. | Amendment of Section 10. |
| 4. After Section 11 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely:-

"11A. Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government is satisfied that- | Insertion of Section 11A. |
| (a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of State tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and | Power not to recover Goods and Service Tax not levied or short-levied as a result of general practice. |

- (b) such supplies were, or are, liable to,-
- (i) State tax, in cases where according to the said practice, State tax was not, or is not being, levied, or
- (ii) a higher amount of State tax than what was or is being, levied, in accordance with the said practice,

the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the State tax payable on such supplies, or, as the case may be, the State tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the State tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.”.

**Amendment of
Section 13.**

5. In Section 13 of the principal Act, in sub-section (3),-
- (i) in clause (b), for the words “by the supplier:”, the words “by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or” shall be substituted;
- (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
- “ (c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:”;
- (iii) in the first proviso, after the words, brackets and letter “or clause (b)”, the words, brackets and letter “or clause (c)” shall be inserted.

**Amendment of
Section 16.**

6. In Section 16 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:-
- (5) “Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under Section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

- (6) Where registration of a registered person is cancelled under Section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under Section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration. the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under Section 39,-
- (i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or
- (ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration, whichever is later.”.
7. In Section 17 of the Principal Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words and figures “Sections 74, 129 and 130”, the words and figures “Section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24” shall be substituted. **Amendment of Section 17.**
8. In Section 21 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section74A” shall be inserted. **Amendment of Section 21.**
9. In Section 30 of the Principal Act, in sub-section (2), after the proviso, for the full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 30.**
- “ Provided further that . such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”. **Amendment of Section 31.**
10. In Section 31 of the Principal Act, in sub-section (3) -
- (a) in clause (f), after the words and figure “of Section 9 shall”, the words “, within the period as may be prescribed,” shall be inserted;

(b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of clause (f), the expression “supplier who is not registered” shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under Section 51.”.

Amendment of Section 35.

11. In Section 35 of the Principal Act, in sub-section (6), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.

Amendment of Section 39.

12. In Section 39 of the Principal Act, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(3) Every registered person required to deduct tax at source under Section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.”.

Amendment of Section 49.

13. In Section 49 of the Principal Act, in sub-section (8), in clause (c), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.

Amendment of Section 50.

14. In Section 50 of the Principal Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.

Amendment of Section 51.

15. In Section 51 of the Principal Act, in sub-section (7), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.

Amendment of Section 54.

16. In Section 54 of the Principal Act,-

(a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted;

(b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(15) Notwithstanding anything contained in this Section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.”.

17. In Section 61 of the Principal Act, in sub-section (3), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 61.**
18. In Section 62 of the Principal Act, in sub-section (1), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 62.**
19. In Section 63 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 63.**
20. In Section 64 of the Principal Act, in sub-section (2), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 64.**
21. In Section 65 of the Principal Act, in sub-section (7), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter ‘or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 65.**
22. In Section 66 of the Principal Act, in sub-section (6), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 66.**
23. In section 70 of the Principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:- **Amendment of Section 70.**
- “(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.”.

Amendment of Section 73.

24. In Section 73 of the Principal Act,—

- (i) in the marginal heading, after the words “Determination of tax”, the words and figures“, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,” shall be inserted;
- (ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(12) The provisions of this Section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.”.

Amendment of Section 74.

25. In Section 74 of the Principal Act,—

- (i) in the marginal heading, after the words “Determination of tax”, the words and figures“, pertaining to the period up to Financial Year 2023-24,” shall be inserted;
- (ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(12) The provisions of this Section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.”.

- (iii) the Explanation 2 shall be omitted.

Insertion of Section 74A.

26. After Section 74 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason pertaining to Financial year 2024-25 onward.

“74A, (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under Section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

- (2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.
- (3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.
- (4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.
- (5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,—
 - (i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten percent of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;
 - (ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.
- (6) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax-interest and penalty due from such person and issue an order.

- (7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

- (8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,—
- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,-

- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen percent of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;
 - (ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five percent of such tax within sixty days of issue of the notice and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;
 - (iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty percent of such tax within sixty days of communication of the order and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.
- (10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub-section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.
- (11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.
- (12) The provisions of this Section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.—For the purposes of this Section,—

- (i) the expression “all proceedings in respect of the said notice” shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons and such proceedings against the main person have been concluded under this Section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded.

Explanation 2.—For the purposes of this Act, the expression “suppression” shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

**Amendment of
Section 75.**

27. In Section 75 of the Principal Act,—

- (a) in sub-section (1), after the words, brackets and figures “sub-sections (2) and (10) of Section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (2) and (7) of Section 74A” shall be inserted;
- (b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of Section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of Section 74A.”;
- (c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of Section 73 or in sub-section (10) of Section 74 or in sub-section (7) of Section 74A.”;
- (d) in sub-section (11), after the words, bracket and figures “sub-section (10) of Section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-section (7) of Section 74A” shall be inserted;

- (e) in sub-section (12), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted;
- (f) in sub-section (13), after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.
28. In Section 104 of the Principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, after the words, brackets and figures “sub-section (2) and (10) of Section 74”, the words, brackets, figures and letter “or sub-sections (2) and (7) of Section 74A” shall be inserted. **Amendment of Section 104.**
29. In Section 107 of the Principal Act,- **Amendment of Section 107.**
- (a) in sub-section (6), in clause (b), for the word “twenty-five”, the word “twenty” shall be substituted;
- (b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.
30. In Section 112 of the Principal Act,— **Amendment of Section 112.**
- (a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the words “from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal”, the words “ or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later.”shall be inserted;
- (b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the words “from the date on which the said order has been passed”, the words “or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later,” shall be inserted;

- (c) in sub-section (6), after the words, brackets and figure “after the expiry of the period referred to in sub-section (1)”, the words, brackets and figure “or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)” shall be inserted;
- (d) in sub-section (8), in clause (b),—
- (i) for the words “twenty percent”, the words “ten percent” shall be substituted;
- (ii) for the words “fifty crore rupees”, the words “twenty crore rupees” shall be substituted.

Amendment of Section 122.

31. In section 122 of the Principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub section (1B), for the words “Any electronic commerce operator, who”, the words and figures “any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under Section 52,” shall be substituted.

Amendment of Section 127.

32. In section 127 of the Principal Act, after the words and figures “Section 73 or Section 74”, the words, figures and letter “or Section 74A” shall be inserted.

Insertion of Section 128A.

33. After section 128 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely:—

Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under Section 73, for certain tax periods.

- “128A. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,—
- (a) a notice issued under sub-section (1) of Section 73 or a statement issued under sub-section (3) of Section 73, and where no order under sub-section (9) of Section 73 has been issued; or
- (b) an order passed under sub-section (9) of Section 73, and where no order under sub-section (11) of Section 107 or sub-section (1) of Section 108 has been passed; or
- (c) an order passed under sub-section (11) of Section 107 or sub-section (1) of Section 108, and where no order under sub-section (1) of Section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub-section (1) of Section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section :

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of Section 107 or under sub-section (3) of Section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of Section 117 or under sub-section (1) of Section 118 or where any proceedings are initiated under sub-section (1) of Section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be,

within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-Section (1) of Section 107 or sub-section (1) of Section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.”.

**Amendment of
Section 171.**

34. In Section 171 of the Principal Act,—

(a) in sub-section (2), for the full stop, colon shall substituted and there after the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:

“ Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, “request for examination” shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.”;

the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“**Explanation 2.**—For the purposes of this Section, the expression “Authority” shall include the “Appellate Tribunal”.”.

35. In Schedule III to the Principal Act, after paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely:—
- Amendment of Schedule III.**
- “9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co- insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the Central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.
10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the Central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.”
36. No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had Section 6 of this Act been in force at all material times.
- No refund of paid tax and reversed input tax credit.**